(ङ) पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान कितने नए उद्योग लगाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्रीमति कृष्णा साही): (क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 41 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी विशेष जिले/क्षेत्र का औद्योगिकीकरण मूलतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार जहां सम्भव होता है उनके प्रयास से सहायता करती है। पर्वतीय तथा दूरदराज के क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए सरकार एक परिवहन राजसहायता योजना संचालित कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विकास केन्द्र योजना जिसमें चने हुए केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सृजन करके उद्योगों के छितराव की व्यवस्था है; के अधीन राज्य सरकार को 8 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं।

(ङ) वर्ष 1990–92 (मई तक) के दौरान उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए जारी किये गये आशय पत्रों (एल. ओ. आई.) और औद्योगिक लाइसेंसों (आई. एल.) की संख्या नीचे दी जाती है:

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1990	74	30
1991	62	11
1992 (मई तक)	13	—

Location of a tyre manufacturing unit at Mangalagiri in Andhra Pradesh

794. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when the letter of Intent was sanctioned to A.P.I.D.C./Government of Andhra Pradesh to set up a tyre manufacturing unit in Mangalagiri;

(b) what steps have been taken to execute the same;

(c) what are the reasons for the undue delay in this regard; and

(d) what steps have been taken to expedite the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SMT. KRISHNA SAHI): (a) A Letter of Intent for manufacture of tyres and tubes was granted to A.P.I.D.C. on 5.2.85 for Mangalagiri in Andhra Pradesh.

(b) Land for construction of the unit has been acquired and possession given to Andhra Pradesh Automobile Tyres and Tuesb Ltd.

(c) and (d) Implementation of the Licence has been delayed because arrangements for technical collaboration/know-how are yet to be tied up.

Exit Policy

795. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Inter-Ministerial Committee at the apex level has recently finalised a "brief" on the country's exit policy as per the news-item entitled "Exit Policy brief finalised" which appeared in *The Times of India*, dated June 2, 1992; and

(b) if so, what are the details in this regard?